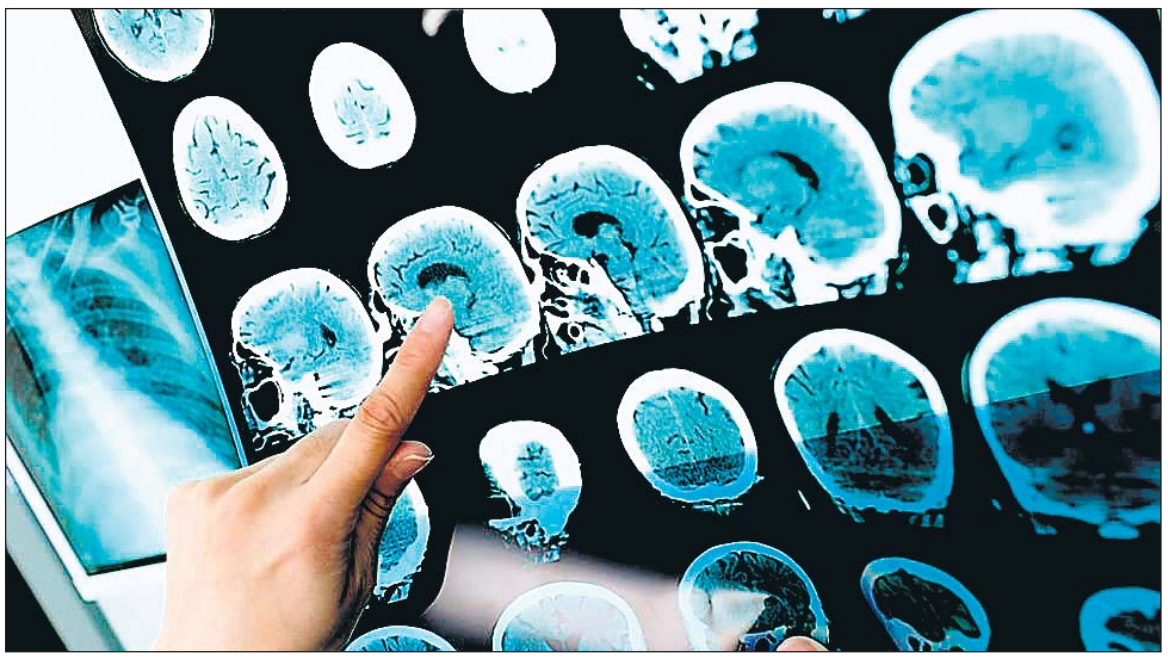

रूटीन ब्रेन स्कैन के दौरान जब एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई उस समय वैज्ञानिकों ने एक अप्रत्याशित खोज की। ब्रेन स्कैन के दौरान मृत्यु के समय उसकी जो ''ब्रेन एक्टिविटी'' हो रही थी, उसका दुर्लभ डेटा भी रिकॉर्ड हो गया। जीवन के अंतिम क्षणों में, व्यक्ति का हार्ट रूकने से 30 सैकण्ड पहले तथा 30 सैकण्ड बाद, उसकी ब्रेन वेव्ज़, मस्तिष्क की उन गतिविधियों के समान थीं, जो सपना देखते समय, मैमोरी रीकॉल तथा मैडिटेशन के समय देखी जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे यह बात सत्य जान पड़ती है कि, मरते समय वास्तव में लोगों की आँखों के सामने ''उनका पूरा जीवन कौंध जाता है।'' मृत्यु जैसा अनुभव कर चुके कई लोगों द्वारा मृत्यु के समय पूर्व स्मृतियों की पुनरावृत्ति की बात कही जा चुकी है। लेकिन यह पहला वैज्ञानिक सबूत है, जो बताता है कि यह ''फ्लैश'' वास्तविक हो सकता है। तथापि, चूँकि यह एक अकेली केस स्टडी है, इसलिए कहना असंभव है कि यह घटना कितनी आम है और इस दौरान जो अनुभव होता है वो क्या है। शोधकर्ताओं ने 2016 में यह चौंकाने वाली खोज उस समय की थी जब वो मिर्गी पीड़ित 87 वर्षीय एक कैनेडियन की मस्तिष्क गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए उसका ई.ई.जी. कर रहे थे। उसी समय मरीज को अचानक जानलेवा हार्ट अटैक हुआ। शोधकर्ताओं ने एक वक्तव्य में कहा कि, मरीज की अप्रत्याशित मृत्यु का तात्पर्य यह था कि, टीम ने अनजाने में मरते हुए आदमी की ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लिया। इससे वैज्ञानिक यह देख पाए कि जब व्यक्ति मर रहा था तब उसकी ''ब्रेन वेव्ज़'' (न्यूरल ऑसिलेशन्स) में कैसे परिवर्तन हुए। उन्होंने पाया कि उसका हृदय रूकने से 30 सैकण्ड पहले व 30 सैकण्ड बाद ब्रेन एक्टिविटी में असामान्य परिवर्तन हुए थे। शोध के समय, कैनेडा में युनिवर्सिटी ऑफ टोरॉन्टो में न्यूरोसर्जन एवं वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. अजमल ज़ैमर ने कहा ''मृत्यु से ठीक पहले व बाद में हमने न्यूरल ऑसिलेशन्स के विशिष्ट समूह में परिवर्तन देखे। विशिष्ट प्रकार के इन ऑसिलेशन्स को गामा वेव्ज़ कहते हैं।'' इन गामा वेव्ज़ के अध्ययन से वैज्ञानिकों को अहसास हुआ कि व्यक्ति अपने सम्पूर्ण जीवन की स्मृतियों को ''रीप्ले'' कर रहा था। इस अद्भुत घटना को ''लाइफ रीकॉल'' के नाम से जाना जाता है।

यू.पी. के अंतिम दो चरण और भी ज्यादा भारी पड़ेंगे भाजपा को?

शायद इसीलिए अब प्र.मंत्री मोदी 3 मार्च से 5 मार्च तक यू.पी. में ही प्रवास करेंगे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के अंतिम दो चरणों से पहले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव प्रचार अभियान में पूरी तरह से कूद गये हैं तथा उन्होंने 3 से मार्च तक राज्य में डेरा डाले रहने का निर्णय लिया है। इस दौरान वे चन्दोली, भदोही, जौनपुर तथा मिर्जापुर सहित कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज उन्होंने महाराजगंज तथ बलिया में सभाएं संबोधित की, जिनमें उन्होंने भाजपा की ''राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा'' बनाम विपक्षी दलों की ''परिवारवादी राजनीति'' को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया।

चूंकि अब तक सम्पन्न हुए मतदान के पांच चरणों में समाजवादी पार्टी, भाजपा पर भारी बताई जा रही है, इसलिए भाजपा ने मोदी के रुप में अपने सबसे ताकतवर प्रचारक को मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश न केवल 2024 के लोकसभा चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं निर्णायक है, बल्कि इसके कुछ तात्कालिक कारण भी है अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहता है तो

- **भाजपा की दिक्कत इसलिए बढ़ गयी है क्योंकि इस बार भी ''मंडल'' थीम प्रभावी हो गयी है इस क्षेत्र में।**
- **एक शिकायत इस संबंध में यह है कि भाजपा ने आरक्षण नीति को ढीला कर दिया है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण के दायरे में लाकर।**
- **पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां औसतन ''लैण्ड होल्डिंग'' 600 वर्ग मीटर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.1 हैक्टेयर है, नौकरी में आरक्षण एक लोकप्रिय व आकर्षक नारा है।**

वह इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पायेगी। भाजपा हल्कों में ऐसी आशंकाए भी दिखाई सुनाई दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार से एक के बाद एक कई प्रभाव हो सकते हैं, जिसके तहत बिहार या हरियाणा में भाजपा की गठबंधन सरकारों में उथल-पुथल संभावित हो सकती है। अगर सपा का प्रदर्शन अपेक्षानुरुप रहता है तो राज्यसभा में भाजपा का संख्या बल भी कम हो जायेगा। मतदान के पहले पांच चरणों की जमीनी रिपोर्ट बताती हैं कि सपा, भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है तथा ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि भगवा पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना बड़ा संख्या बल कायम नहीं रख पायेगी। शेष दो चरणों में भाजपा के लिए और भी बड़ी चुनौतियां मानी जा रही हैं। शेष दोनों चरणों वाले क्षेत्रों में ''मंडल राजनीति'' का मंथन दिखाई दे रहा है। इन क्षेत्रों का मतदाता बेरोजगारी महंगाई तथा आवारा पशुओं की समस्या से व्यथित है। रविवार को हुए मतदान के पांचवे चरणों में भी, गायों का मुद्दा प्रचार के एक बड़े मुद्दे के रुप में सामने आया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक निर्धनता-पीड़ित एवं पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। वहां एक व्यक्ति के पास औसतन 600वर्गमीटर जमीन है, जबकि राष्ट्रीय औसतन 1.1 हैक्टेयर व्यक्ति है। छठे तथा सातवें चरण के मतदाताओं जिनके पास जमीन के टुकड़े छोटे-छोटे तथा बिखरे हुए हैं, के लिए सबसे ज्यादा संकट आवारा गायों से है। यह मुद्दा इस क्षेत्र के लिए बहुत दमदार एवं विशेष चिंता का कारण बना हुआ है।

2017 के चुनावों में भाजपा ने इस इलाके में अपने सतरंगे गठबंधन के बल पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। भाजपा गैर-यादव ओबीसी तथा गैर-जाटव अनुसूचित जातियों को अपने घेरे में लेने में सफल रही थी। इस, बार स्थिति बदली हुई है क्योंकि पिछड़ों तथा ओबीसी इन वर्गों का कई कारणों से भाजपा से मोह भंग हो चुका बताते हैं। इन कारणों में उनकी यह शिकायत भी शामिल है कि केन्द्र सरकार ने आरक्षण नीति को बहुत ''हल्का'' या ''कमजोर'' कर दिया है क्योंकि इस श्रेणी में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग भी शामिर कर दिये गये हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्वकाल में, इन वर्गों पर अत्याचारों एवं उनके उत्पीड़न के बहुत से मामले भी सामने आये हैं।

सुशील आसोपा ने भी राजनैतिक नियुक्ति नामंजूर की

Sushil Asopa @SushilAsopa · 6m
जो राजनैतिक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मुझे आज दी गई है उसे मैं अस्वीकार करता हूँ क्योंकि मेरी सहमति नहीं ली गई। मैं 42 महीने की नौकरी छोड़कर पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया। जीवन भर नि:स्वार्थ सेवा करता रहूंगा।
@ajaymaken @ashokgehlot51

जयपुर, 28 फरवरी (का.प्र.)। राजस्थान में कांग्रेस की राजनैतिक नियुक्तियों में साधारण सदस्य बनाये जाने पर राजेश चौधरी ने भी यह पद नामंजूर कर दिया है।

वहीं एक अन्य ट्वीट में सुशील आसोपा ने भी लिखा कि ''जो राजनैतिक नियुक्ति राज्य सरकार ने मुझे आज दी है, उसे मैं अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी सहमति नहीं ली गई। मैं 42 महीने की नौकरी छोड़कर पदों के लिये कांग्रेस में नहीं आया। जीवन भर नि:स्वार्थ सेवा करता रहूंगा।''

जो नेता चेयरमैनशिप की दौड में थे, उन्हें साधारण सदस्य बनाकर राजनीतिक रुप से कमजोर किया

74 राजनीतिक नियुक्तियों में सिर्फ तीन चेयरमैन बनाए, इनमें अर्चना शर्मा को मिला मजबूत पद

जयपुर, 28 फरवरी (का.प्र.)। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की एक और सूची सामने आई है। इस सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 74 लोगों को नियुक्तियां दी हैं। सूची की खासियत यह है कि जो लोग बोर्ड, निगम व आयोगों में चेयरमैन बनने की दौड़ में थे उन सब को साधारण सदस्य बनाकर राजनीतिक रूप से कमजोर करने का काम किया गया है। सदस्य बनाते समय भी किसी भी नेता के कैडर या वरिष्ठता का भी ध्यान नहीं रखा गया और जहां पूर्व विधायक या पूर्व महापौर को सदस्य

- **सूची जारी होने के साथ ही विरोध भी आया सामने, कई सदस्य दे सकते हैं इस्तीफा।**

बनाया गया है, वही साधारण कार्यकर्ताओं को भी सदस्य बनाकर उनके बराबर खड़ा कर दिया गया है।

विधायक सुरेश मोदी को राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष और विधायक गजराज खटाणा को भवन एवं अन्य सनिर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और यह दोनों ही समितियां नई बनाई गई है। इसी तरह से डॉ.अर्चना शर्मा को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष व मीनाक्षी चंद्रावत को उपाध्यक्ष, सुचित्रा आर्य को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज, दर्शन सिंह गुर्जर को राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग का उपाध्यक्ष और अवधेश दिवाकर बैरवा को राजस्थान अनुसूचित जाती वित्त विकास आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस राजनीतिक सूची की खास बात यह है कि चेयरमैनशिप की दौड़ में लगे सऊद सईदी, राजेश चौधरी, डॉ निजाम मोहम्मद, चयनिका उनियाल,महेश मोरदिया, कैलाश सोयल, अभिमन्यु पूनिया,करण सिंह उचियार, डॉ.ज्योति खंडेलवाल व घनश्याम मेहर को सिर्फ बोर्ड-निगमों में साधारण सदस्य बनाया गया है।

सूची में कुछ विधायकों को निगम-बोर्ड के अध्यक्ष पद दिया गया है, तो कईयों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया गया है।

राजेश चौधरी ने अस्वीकार की राजनैतिक नियुक्ति

राजेश चौधरी is with **Pourush Bhardwaj** and **34 others**.
Just now ·

कांग्रेस आलाकमान ने मुझे राजनीतिक नियुक्ति के जरिए जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करता हूँ ,धन्यवाद देता हूँ।

मैं अपरिहार्य कारणों से यह जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हूँ एवं आग्रह करता हूँ कि मेरे स्थान पर अन्य किसी सक्रिय कोंग्रेसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए।

अन्य कोंग्रेसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है तो मैं कांग्रेस आलाकमान का आभारी रहूंगा। मैं कोंग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा।

धन्यवाद।

#राम_राम_सा

राजेश चौधरी

जयपुर, 28 फरवरी (का.प्र.)। राजस्थान में कांग्रेस की राजनैतिक नियुक्तियों में साधारण सदस्य बनाये जाने पर राजेश चौधरी ने यह पद अस्वीकार कर दिया है। ट्वीट के जरिये राजेश चौधरी ने लिखा ''कांग्रेस आलाकमान ने मुझे राजनीतिक नियुक्ति के जरिये जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिये मैं कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लिखा कि अपरिहार्य कारणों से यह जिम्मेदारी लेने में मैं असमर्थ हूं एवं आग्रह करता हूं कि मेरे स्थान पर किसी अन्य सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता को यह मौका दिया जाना चाहिये। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिये हमेशा उपलब्ध रहूंगा।''

यूरोप बदल गया यूक्रेन पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर शपथपूर्वक शस्त्र त्याग चुके जर्मनी ने इस नए परिदृश्य में रक्षा तैयारियों के लिए भारी व्यय की घोषणा की है।

जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और पूर्व में एक जबर्दस्त सैन्य शक्ति रहा है। इस देश के फिर से व पुन: सैन्यकरण ने ई.यू. को प्रभावित किया है। वस्तुत: स्विट्ज़रलैंड, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी तटस्थ रहा था, ने आज यूरोपीय गठबंधन में शामिल हो गया और रूस के किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन से सभी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया।

इस बदलाव की मान्यता में, ई.यू. ने अब घोषणा कर दी है कि वह यूक्रेन को युद्ध के लिये हथियार सप्लाई करेगा, जिनमें एंटी टैंक मिसाइल तथा उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान सम्मिलित हैं ताकि रूसी वायु सेना जमीन पर अपने सैनिकों को सुरक्षा घेरा उपलब्ध न करा सके। यूक्रेन को कुछ ड्रोन भी भेज दिये गये हैं, तथा ऐसी खबरें हैं कि कुछ रूसी गतिविधियों पर ड्रोनों से हमले किये गये हैं। टैंक, सैनिक तथा बख्तरबंद गाड़ियाँ बड़ी मात्रा में, अनेक किलोमीटरों की यात्रा करने के बाद यूक्रेन की राजधानी पहुँच रही हैं। ई.यू. यूक्रेन सरकार के रूसियों से लड़ने के आग्रह पर एक-एक कदम बढ़ा रहा है। यूक्रेन ने अनुरोध किया है कि रूसियों की भू-आकाशीय (जिओ-स्पेशियल) गतिविधियों की ज़मीनी जानकारी उसे उपलब्ध कराई जाती रहे। ई.यू. अपना जिओ-स्पेशियल मॉनिटरिंग केन्द्र स्पेन में स्थापित कर रहा है ताकि यूक्रेन को, उसके युद्ध संबंधी प्रयासों के लिये इस प्रकार की उपयोगी सुरक्षा-संबंधी जानकारियाँ उसे उपलब्ध कराई जा सकें। लेकिन आर्थिक प्रतिबंध रूस को आर्थिक विनाश की ओर ले जा रहे हैं तथा इन आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर रूसी राष्ट्रपति के सामने गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इन आर्थिक प्रतिबंधों के असर से टकराते हुये, रूसी राष्ट्रपति लोगों का ध्यान अन्य जोखिमों/संकटों की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी तरफ, रूसी राष्ट्रपति ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेन्स फोर्स को ''हाई अलर्ट'' पर कर दिया है। सुरक्षा-विशेषज्ञ इसे पश्चिम के लिये इस तगड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं कि वह इस युद्ध में हस्तक्षेप न करे।

लेकिन कुछ रक्षामंत्रियों ने इस विचार को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह तो रूस की एक रणनीति मात्र है ताकि वह, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटा सके।

वे रूसी राष्ट्रपति के बयान को इस रूप में देख रहे हैं कि युद्ध जिस दिशा में चला गया है, यह बयान उस दिशा और स्थिति के प्रति पुतिन की घोर हताशा को व्यक्त करने वाला है। पाँच दिन हो गये, लेकिन रूस को इस युद्ध से कोई बहुत भारी लाभ नहीं हुआ है, उसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। वस्तुस्थिति हो भी हो, युद्ध अब भिन्न रास्ते पर चला गया है तथा अब उसे रोकना बड़ा कठिन हो गया है। ई.यू. ने रूसी विमानों के लिये अपने हवाई क्षेत्र पर रोक लगा दी है। इस कदम से रूसी एयरलाइनें बहुत अशक्त हो गई हैं।

एक साथ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लैफ्टिनेट जनरल माइकल नगाटा के अनुसार रूस ने अपने यूक्रेन आक्रमण में गंभीर चुनौती पेश करने वाले सायबर अटैक भी किए हैं, जबकि ऑनलाइन दुष्प्रचार यदि सफल हो जाता है तो एक स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है।

'मान प्रतिष्ठा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद, अर्थात 9 मार्च को की जाए। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों को हटाने के लिए दायर की गयी है जो इस अदालत ने उनके खिलाफ 26 मार्च, 2021 के अपने फैसले में की थी। अदालत ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से उनको हटाने के ग्रुप के फैसले को कायम रखा था।

यह बैंच जिसमें न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना तथा हिमा कोहली भी शामिल हैं, उस फैसले पर दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें नैशनल कंपनी लॉ एपैलेट ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.ए.टी.)के दिसम्बर 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिस आदेश में मिस्त्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया गया था। बैंच को उस पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करनी थी, जो शापूरजी पल्लोन जी ग्रुप ने दायर की हैं तथा जिसमें टाटा सन्स तथा सायरस मिस्त्री के बीच के विवाद में खुली अदालत में दिये आदेश को चुनौती दी गयी है।

आदेश कहता है:''पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है। पुनरीक्षण याचिकाएं बुधवार, 9 मार्च 2022 के लिए सूचीबद्ध कर दी जाएं।''

वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास ने मिस्त्री की ओर से कहा कि निर्णायक सुनवाई में मिस्त्री के खिलाफ की गयी कुछ टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा चरित्र पर प्रभाव पड़ा है। उधर, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने टाटा ग्रुप की ओर से इस याचिका को स्वीकार किये जाने पर सवाल खड़े किये।

मिस्त्री तथा उनका शापूरजी पालोन जी ग्रुप, जो एक जानी मानी भवन निर्माता कंपनी है, ने अप्रैल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर, इस अदालत के 26 मार्च के फैसले पर पुर्नविचार की मांग की थी, जिसमें टाटा सन्स के उस निर्णय का समर्थन कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत टाटा सन्स के छटे चेयरमैन पद से अक्टूबर 2016 में मिस्त्री को हटा दिया गया था। मिस्त्री इस पद पर दिसम्बरस 2021 में आसीन हुए थे, जब रतन टाटा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी थी। मिस्त्री के बाद से इस समय तक एन चन्द्रशेखरन टाटा सन्स के एग्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन हैं।

आज से अमूल दूध दो रू. लीटर महंगा हुआ

आनंद (गुजरात), 28 फरवरी (वार्ता)। अमूल ब्रांड के नाम से दूध और दूध उत्पादों के विपणनकर्ता गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने देश भर में कल से अपने अमूल फ्रेश ब्राण्ड के दूध की क़ीमत में दो रुपए प्रति लीटर बाढ़ोत्तरी का फ़ैसला किया है।

अमूल की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार अमूल फ्रेश, देश भर

- **पिछले 2 वर्षों में अमूल ने अपने दूध की कीमतों में प्रति वर्ष केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि की है।**

के जिन भी बाज़ारों में उपलब्ध है, वह उसकी कीमत में उक्त वृद्धि के अलावा गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र क्षेत्र के बाज़ारों में कल यानी एक मार्च से अमूल गोल्ड, ताज़ा और शक्ति की क़ीमतों में भी वृद्धि की गयी है। गोल्ड की कीमत रु. 30 प्रति 500 मि.ली., अमूल ताजा रु. 24 प्रति 500 मि.ली. और अमूल शक्ति रु. 27 प्रति 500 मि.ली. होगी।

बेलारूस बॉर्डर पर रूस व यूक्रेन के बीच तीन घंटे बातचीत हुई

मॉस्को/यूक्रेन, 28 फरवरी। यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस बॉर्डर पर हुई शांति वार्ता तीन घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली। बातचीत के दौरान यूक्रेन ने अपनी ओर से रूस के सामने यह शर्त रखी की रूस जल्द से जल्द अपनी पूरी सेना को वापस बुलाये। मीटिंग में दोनों ओर के प्रतिनिधिमंडल ने अपना-अपना पक्ष रखा और उसके बाद तय हुआ है कि, किसी अंतिम फैसले पर पहुंचने के लिए आगे एक और मीटिंग रखी जायेगी।

- **बातचीत में कोई फैसला तो तय नहीं हुआ लेकिन यूक्रेन ने रूस से कहा कि, रूस जल्द से जल्द अपनी सेना वापस बुलाये।**

मीटिंग के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अपने-अपने देश वापस लौट गये जहां वे मीटिंग में रखी गई बातों को अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचायेंगे।

इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के सैनिकों से जल्द से जल्द देश (यूक्रेन) छोड़ देने के लिए कहा है। जेलेंस्की ने अपने एक वीडियो संबोधन में यह चेतावनी दी। इससे पहले उन्होंने सोमवार को बेलारूस में मॉस्को और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति वार्ता के मद्देनजर अगले 24 घंटे की अवधि को अहम बताया था।

उन्होंने कहा कि, करीब साढ़े चार हजार रूसी सैनिक मार गिराए गए हैं और अब यह आंकड़ा बढ़कर 5,300 हो गया है। उन्होंने कहा , अपने हथियार डाल दें और देश छोड़ दें। अपने कमांडर्स और प्रचारकों पर विश्वास न करें, सिर्फ अपनी जिंदगी बचाए-देश छोड़ चले जाए।

यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह संदेश बेलारूस में इस वक्त जारी शांति वार्ता से पहले आया है। यूक्रेन ने कहा है कि, देश की जेलों में बंद कैदियों को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए रिहा किया जाएगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि युद्ध का अनुभव रखने वाले यूक्रेनी कैदियों को लड़ाई वाले स्थानों पर भेजने के लिए जेल से रिहा किया जाएगा।

धारीवाल ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सही सलामत स्वदेश लाया जायेगा। उन्होंने बताया यूक्रेन में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की सहायता करने व उन्हें घर तक लाने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली, मुम्बई सहित प्रमुख स्थानों पर अधिकारियों को नियुक्त कर उनकी जिम्मेदारी तय की है।

उन्होंने अभिभावकों को बताया कि बच्चों के घर तक लाने का सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

उन्होंने सभी बच्चों को एम्बेसी के सम्पर्क में रहकर उनकी सलाह के अनुसार वाहनों से यात्रा कर समीप के देशों तक पहुंचने का सुझाव दिया। छात्रा हिमांशी ने बताया कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे 200 से अधिक विद्यार्थियों ने कीव में जाकर एम्बेसी में शरण ली थी, जहां खाने-पीने की समस्या आने पर उनकी सलाह के अनुसार ट्रेन से रोमानिया जाने का निर्णय लिया गया। छात्रा ने बताया कि वे रेलवे स्टेशन से रोमानिया के लिए रवाना होने वाले हैं।

असर दिखाने लगी है ''इकोनॉमिक पाबंदियों''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

630 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है जिससे यह आयात का भुगतान और युद्ध को फंडिंग कर सकता था।

लेकिन सैन्ट्रल बैंक के संसाधनों की फ्रीज कर दिया गया है इसका अर्थ है कि बैंक के पास यह फंड नहीं है। इनमें से अधिकांश संसाधन बॉण्ड, सिक्युरिटीज़ और स्वर्ण के रूप में रशियन बैंक के पास हैं जो अब इसकी पहुंच में नहीं है।

इसकी वजह से रूस की मुद्रा रूबल डॉलर के मुकाबले 30 प्रतिशत तक लुढ़क गई। सैन्ट्रल बैंक ने मूल ब्याज दर 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी है जो अभूतपूर्व है। इसका अर्थ है कि रूस में जो भी बिज़नैस या उद्योग बचा है वह टिक नहीं सकता है।

इन वित्तीय कदमों ने रूस के वित्तीय व्यवस्था के लिए एक तरह से मृत्युदण्ड लिख दिया है।

मॉस्को स्टॉक एण्ड फाइनैंशियल मार्केट्स अथॉरिटीज़ ने सोमवार को बाजार नहीं खोला ताकि बाजार में संभावित भारी गिरावट को रोका जा सके। यूरोपियन एक्सचेंज में अधिसूचित रूसी कंपनियों के शेयर मूल्य बाजार खुलने के साथ ही गिरने तय है। इसका अर्थ है कि कंपनियां वित्तीय रूप से दिवालिया हो जाएंगी।

ब्रिटिश पैट्रोलियम, जो रूस की सबसे बड़ी तेल व गैस ऑपरेटर कंपनी रॉज़नैफ्ट में 20 प्रतिशत शेयर होल्डर है, पहले ही अपने एग्ज़िट की घोषणा कर चुकी है। अगर ब्रिटिश पैट्रोलियम अपने स्टॉक का बड़ा भाग बाजार में छोड़ देती है तो बाजार तेजी से गिर जाएगा।

रूस से मिल रही खबरों के अनुसार ए.टी.एम. और बैंकों के बाहर पैसा निकालने वाले लोगों की कतारें लगी हैं। लेकिन बैंकों के पास पर्याप्त फंड नहीं है। बैंकिंग अथॉरिटीज़ ने पैसा निकाले जाने की एक सीमा तय कर दी है।

इन हालात में अगर बैंक, खासकर वे जिनकी पहुंच नकद पूंजी तक नहीं है, आशंकित हैं तो यह अनुचित भी नहीं है। लेकिन इन हालात में अन्य बैंक भी रूस के बैंकों से लेन-देन करने में डरेंगे। इनके साथ कोई भी डील करने से वे कानूनी विवाद और प्रतिबंधों में फंस सकते हैं। इसीलिए रूसी बैंकों के साथ डील करना खतरनाक है।

हालात और चर्चा यह है कि रूस को अभी कहां से सहायता मिल सकती है।

चर्चा है कि क्या चीन आगे आकर रूस की मदद करेगा। चीन का 3 ट्रिलियन डॉलर का भारी विदेशी मुद्रा भंडार है और यह रूस की इस समय मदद कर सकता है। इन अटकलों का मुख्य कारण यह है कि इस संकट से पहले ही चीन ने रूस को सहायता देना आरंभ कर दिया था। रूस उन चंद देशों में से एक है जिसने बीज़िंग में हुए विंटर ओलम्पिक्स में भाग लिया था और निकट सहयोग व सहायता का संयुक्त बयान जारी किया था। रूस-चीन के सहयोग के दायरे से कुछ भी परे नहीं है।

अब जब संकट आ गया है चीन उत्सुकता से देख रहा है कि उसका समर्थन कैसे काम करेगा।

अभी तक चीन के सभी बैंक और इकोनॉमिक इकाइयां किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों के उल्लंघन से दूर हैं ना ही चीन ने किसी भी प्रकार के वित्तीय समायोजन की पेशकश की है। इसके विपरीत इन बैंकों ने प्रतिबंधों की व्यवस्था का पालन किया है।

हालांकि चीन की बड़ी कंपनियां या बैंकों का निर्णय राजनैतिक फैसला होगा। चीन के बड़े बैंक, खासकर सरकारी बैंक राजनैतिक निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि मौजूदा हालात में वे काफी सतर्क हैं क्योंकि प्रतिबंधों का ज़रा सा भी उल्लंघन उन्हे भी संकट में डाल सकता है।

चीन की कंपनियों ने दुनिया भर में पैसा लगा रखा है और वे पहले से ही अमेरिका के दबाव का सामना कर रही हैं और अब वे परिणामों के प्रति चिंतित हैं। वित्तीय हथियारों के अलावा ई.यू. ने अपने समूचे एयर स्पेस को रूसी विमानों, चाहे वे सैन्य विमान हो या प्राइवेट जैट, के लिए ''नो फ्लाइज़ोन'' घोषित कर दिया है। इसका अर्थ है कि रूस को पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया और नाटो के विमान रूस सीमा के पास से उड़ान भर रहे है।

जिओ इकोनॉमिक हथियारों के उपयोग का सामाजिक व राजनैतिक प्रभाव भी होगा। सोवितय संघ के विघटन के बाद से रूस में बहुत ज्यादा अमीरों का एक वर्ग उभरा है जो पश्चिमी देशों जैसी जीवन शैली का आदी है। वे यूरोपियन देशों में घूमते हैं, खरीददारी करते हैं यूरोपियन शेयरों में पैसा लगाते हैं अपने निजी विमानों में सफर करते है।

इन भौगोलिक-आर्थिक प्रतिबंध से इन अमीरों की दुनिया चरमरा जाएगी। वे अपने ही देश में कैदी बन जाएंगे, जिसका उनके देश में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इनमें से कई तो रूस में पुतिन शासन के मददगार हैं। देखना यह होगा कि अब हालात क्या रूप लेते है।

जाली...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आईदान चारण निवासी मण्डला चारण एवं सोनू गोस्वामी पुत्र भगवान निवासी लदाना थाना फतेहनगर उदयपुर हाल धिनवा थाना सदर को गिरफ्तार किया गया। सोनू गोस्वामी के विरुद्ध पूर्व में थाना फतहनगर पर मुकदमा दर्ज है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600